प्रेस विज्ञप्ति

06 मार्च, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा विधायक, हरियाणा ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

भाजपा सरकार ने हरियाणा को 'दीवालिएपन के कगार' तथा 'भारी कर्ज के चक्रव्यूह' में धकेल दिया है।

पिछले दो सालों में राज्य पर कर्ज का भार 'रोजाना 74 करोड़ रु.' की दर से बढ़ा है; पिछले दो सालों में कर्ज लगभग दोगुना होकर 1,25,000 करोड़ रु. हो गया है।

खट्टर सरकार ने 'कर्ज से भरपूर – विफल' बजट पेश किया है। भाजपा सरकार का तीसरा बजट काफी निराशाजनक, नकारात्मक वृद्धि वाला और जन–विरोधी है। हरियाणा के लोग, जिनमें अर्थव्यवस्था–बिज़नेस–कृषिकर्मी–युवा शामिल हैं, ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसमें ना तो भविष्य के लिए कोई योजना है और न ही कृषि, छोटे दुकानदारों को कोई राहत दी गई है, न ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है।

केवल दो वर्ष में ही भाजपा सरकार ने संपन्न और फलते–फूलते हरियाणा राज्य को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हरियाणा के लोगों को यह जानकर बड़ा धक्का लगा है कि सरकार की अकमर्ण्यता, अंदरूनी कलह, चुनाव से पहले किए गए किसी भी वायदे को पूरा न करने के बावजूद हरियाणा राज्य पर कर्ज भी पिछले दो सालों में बढ़कर दोगुना हो गया है।

बजट में सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि प्रदेश पर कर्ज 2014–15 में 70,931 रु. से बढ़कर 2016–17 में 1,24,935 करोड़ रु. हो गया है, जो कि 2014–15 के मुकाबले 55,000 करोड़ रु. ज्यादा है। केवल एक साल में ही कर्ज 1,14,048 करोड़ रु. (2015–16) तक पहुंच गया था। ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस सरकार के दस सालों के कार्यकाल में हरियाणा का सर्वांगीण विकास हुआ, समाज के सभी वर्गों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गईं, इसके बावजूद दस सालों में राज्य का कर्ज 55,000 करोड़ रु. से भी कम बढ़ा था। अब स्थिति बहुत गंभीर तथा चिंताजनक बन गई है कि राज्य का कर्ज औसतन 74 करोड़ रु. प्रतिदिन की दर से बढ़ते हुए 1,25,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगले वर्ष के लिए खट्टर सरकार ने घोषणा की है कि कर्ज 2017–18 में 1,41,854 करोड़ तक बढ़ जाएगा, लेकिन स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह है। क्योंकि बजट में वित्तीय घाटा 2016–17 में 2.49% से बढ़कर 2017–18 (प्रस्तावित) में 2.84% की संभावना भी व्यक्त की गई है। इससे साफ होता है कि अगले एक साल में प्रदेश के कर्ज में 30,000 करोड़ तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, जिससे राज्य के लोगों पर और अधिक भार पड़ेगा।

बजट के बिंदुवार अध्ययन से साफ हो जाता है कि यह कितना खोखला है। बजट में चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें लोगों को गुमराह

करने के लिए केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है। बजट में 8,483 करोड़ रु. के छिपे हुए टैक्स का प्रस्ताव भी किया गया है, जिससे 2017–18 में लोगों की जेबों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 2016–17 में टैक्स कलेक्शन में 60,327 करोड़ रु. हुआ है, जिसे 2017–18 में बढ़ाकर 68,810 करोड़ रु. दिखाया गया है। हरियाणा के बजट के ऐतिहासिक आंकड़े टैक्स से राजस्व में 14% की वृद्धि की परिकल्पना का समर्थन नहीं करते।

गौरतलब है कि कैपिटल रिसीप्ट्स में 7,459 करोड़ रु. की कमी आई है, जिससे भाजपा सरकार की वित्तीय नासमझी और राजकोषीय कुप्रबंधन की झलक मिलती है। 'कैपिटल रिसीप्ट' 2015–16 में 31,142 करोड़ रु. से घटकर 2016–17 में 23,683 करोड़ रु. हो गया है।

इसी तरह 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' तथा 'एस्सेट निर्माण' पर सरकार के ध्यान की कमी इस बात से साबित हो जाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 8,575 करोड़ रु. की कमी कर दी गई है। कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर सन 2015–16 में 20,158 करोड़ था, जिसे घटाकर 2016–17 में 11,583 करोड़ रु. कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण तथा एस्सेट कॉन्सट्रक्शन में कमी आई है, जो कि राज्य के विकास की पहली शर्त मानी जाती है।

'दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना' तथा 'मंगल नगर विकास योजना' केवल सरकार द्वारा दी गई 'लॉलीपॉप' हैं, क्योंकि इनके लिए सरकार ने पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की है। राज्य में लगभग 6,000 गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 3,000 से 10,000 के बीच है, लेकिन 1500 गांवों के लिए केवल 1200 करोड़ रु. ही दिए गए हैं। यह भी दुख की बात है कि पैसे की व्यवस्था नाबार्ड से मिले एक लोन द्वारा की जानी है, जिसकी शर्तें अभी भी साफ नहीं हैं। ''अच्छा होता कि यह प्रबंधन खर्चों में बचत करके किया जाता; सच्चाई है कि झूठ परोसा जा रहा है।'' भाजपा सरकार केवल खोखले और लुभावने वायदे करके लोगों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रही है।

बढ़ते हुए बजट घाटे की सबसे अधिक बुरी बात यह है कि पिछले दो सालों में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरु नहीं किया गया, यहां तक कि पहले से चल रहे बड़े प्रोजेक्ट भी रोक दिए गए हैं। भाजपा ने चुनाव से पहले किया गया अपना कोई भी वायदा भी पूरा नहीं किया और कांग्रेस सरकार द्वारा शुरु गई जनकल्याणकारी योजनाओं में अड़चनें डाली गईं। चिंता की बात है कि राजकोष को चुपचाप लूटा जा रहा है, जिससे कर्ज दोगुना हो गया है। **समय की जरूरत है कि प्रदेश सरकार तेजी से बढ़ते कर्ज पर एक श्वेतपत्र जारी करके स्थिति स्पष्ट करे।**